International Journal of Contemporary Research in Multidisciplinary; 2023; 2(5): 62-65

Review Article

भूमंडलीकरण के दौर में उत्तर-औपनिवेशिक राज्य

Author (s): डॉ. नरेंद्र सीमतवाल[1*], महेन्द्र कुमार वर्मा[2]

[1]*सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय कन्या महाविद्यालय, किशनगढ़, अलवर, राजस्थान, भारत*

[2]*सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, अलवर, राजस्थान भारत*

Corresponding Author: * डॉ. नरेंद्र सीमतवाल

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10937604

सारांश

यह शोध पत्र मुख्यतः इस पत्र पर केंद्रित है कि उपनिवेशवाद में औपनिवेशिक राज्यों के निर्माण और कामकाज को कैसे प्रभावित किया ? राज्य के उत्तर औपनिवेशिक शासन के परिणाम ने राज्यों की राजनीति, समाज, संरचनाओं को कैसे प्रभावित किया? सांस्कृतिक, साम्राज्यवाद और आर्थिक शोषण अभी भी औपनिवेशिक समाज को प्रभावित करते हैं । वैश्वीकरण के दौर में राष्ट्र-राज्य की अवधारणा समित हो रही है या राज्य का स्वरूप अग्रगामी हो रहा है या पच्छ गामी । अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में उत्तर-औपनिवेशिक राज्यों की भूमिका और प्रभाव का विश्लेषण करना। इस अध्ययन में क्षेत्रीय और ग्लोबल स्तर पर भूमंडलीकरण के प्रकार, प्रक्रिया, और परिणामों को विस्तृत रूप से विश्लेषित किया जाएगा। अंततः, इस शोध का उद्देश्य है उत्तर-औपनिवेशिक राज्यों के भूमंडलीकरण में सुधार के लिए नीतिगत सिफारिशें प्रस्तुत करना ।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2583-7397
- **Received:** 26-08-2023
- **Accepted:** 25-10-2023
- **Published:** 30-10-2023
- **IJCRM:**2(5);2023:62-65
- **©2023, All rights reserved**
- **Plagiarism Checked**: Yes
- **Manuscript ID:** IJCRM:2-5-16
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Manuscript

डॉ. नरेंद्र सीमतवाल, महेन्द्र कुमार वर्मा. भूमंडलीकरण के दौर में उत्तर-औपनिवेशिक राज्य International Journal of Contemporary Research in Multidisciplinary. 2023; 2(5):62-65.

कूटशब्द: उपनिवेश, साम्राज्य, राष्ट्र, भूमंडलीकरण, प्रकृति, शोषण, प्रौद्योगिकी, विरासत प्रभुसत्ता, परिधि, नीतियाँ, गरीबी, उत्पादन, राजनीतिक प्रवृत्तियाँ, उत्पादक संरचना, आर्थिक विकास, सामाजिक असमानता, क्षेत्रीय, वैश्विक स्तर, नीतिगत सिद्धांत ।

प्रस्तावना:

इस समय में विश्व समुदाय में उपनिवेश विरोधी संवेदना का उदय हुआ । विशेष कर दो विश्व युद्ध के बाद उत्तर औपनिवेशिक राज्य अस्तित्व में आए जिन्होंने अपने स्वतंत्रता की लड़ाई लडी । अपने राष्ट्रीय संघर्ष और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से आजादी हासिल की उन्हें मुख्यतः तीसरी दुनिया के देश भी कहा जाता है। विभिन्न लेखकों द्वारा राज्य को विभिन्न पदावलियों से पहचाना जाता है जैसे- नव पैतृक राज्य, कमजोर राज्य, युद्ध प्रभावित अर्थव्यवस्था, अर्थ राज्य ।

औपनिवेशिक राज्यों की प्रकृति को समझने से पहले जरूरी है कि हम उत्तर उपनिवेशवाद को समझें । उत्तर उपनिवेशवाद क्या है? दरअसल यह एक सैद्धांतिक ढांचा है जो 20 वीं सदी के मध्य से अंत तक तक मुख्य रूप से उपनिवेशवाद की विरासत के जवाब में उभरा। उपनिवेशों के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव मुख्यतः बाहरी निर्धारकों द्वारा निर्धारित किए गए ।

उत्तर-उपनिवेशिक राज्य का इतिहास

उपनिवेशवाद

वह स्थिति या प्रवृति है जिसमें उन्नत एवं शक्तिशाली राष्ट्र किसी पिछड़े हुए देश पर अपना प्रभुत्व और शासन स्थापित कर लेते हैं। वहां के उच्च प्रशासनिक पदों और मूल्यवान संसाधनों पर उनका नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं ।

नव उपनिवेशवाद

पश्चिम के पूंजीवादी देशों की वह रणनीति जिसमें वह विकासशील देशों पर अपना राजनीतिक आधिपत्य कायम नहीं करते बल्कि मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विदेशी सहायता के माध्यम से उन देशों को सस्ते कच्चे माल, सस्ते श्रम के रूप में इस्तेमाल करते हैं । एशिया, अफ्रीका या लैटिन अमेरिका के देश प्राकृतिक संसाधनों और श्रम शक्ति से संपन्न थे परंतु उन्हें न तो आधुनिक शिक्षा प्राप्त हो पाई थी न वे अपने आप को राष्ट्रों के रूप में संगठित कर पाए थे । भारत और मिश्र अपने गौरवशाली अतीत के लिए विख्यात थे परंतु 18वीं शताब्दी के मध्य में न तो वे राष्ट्रों के रूप में संगठित होने में सक्षम थे, न वे अपना आधुनिकीकरण करने की क्षमता रखते थे। तत्कालीन यूरोप के देशों को इन पर आधिपत्य स्थापित करने में कोई मुश्किल नहीं हुई। तृतीय दुनिया के देश उपनिवेशवाद के पंजे में पहुंच गए। पश्चिमी देश अपनी बेईमानी से यह सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि वह अपने इतिहास, भाषा, साहित्य और प्रौद्योगिकी की दृष्टि से विश्व में सर्वश्रेष्ठ है । उपनिवेशवादी राष्ट्र आदिवासी लोगों को सभ्यता का लाभ पहुंचाने का महान दायित्व पूरी पूरा कर रहे थे जिसे उन्होंने श्वेत जाति का भार की संज्ञा दी । उपनिवेशवादी शक्तियां अपने उपनिवेशों में शैक्षिक और प्रशासनिक ढाँचा स्थापित करती है।उनके अंधविश्वास या जनता के को मिटाती है ताकि वह भरपूर शोषण कर सकें । लेकिन उपनिवेशित देश धीरे-धीरे अपनी संस्कृति से परिचित होते हैं तथा उनके मन में राष्ट्रवादी भावना का संचार होता है और वह राष्ट्रीय आंदोलन के लिए तैयार हो जाते हैं। तब तक उपनिवेशवादी राष्ट्र अपरिचित अपना पूरा लाभ उठा चुका होता है। अतः वह उपनिवेश को स्वाधीनता प्रदान कर देता है और शोषण के एक नए तरीकों का आविष्कार कर लेता है जिन्हें नव उपनिवेशवाद की संख्या दी जाती है । वैसे उपनिवेश बनाए गए देश के लोगों को राजनीतिक स्वाधीनता मिल जाने का मतलब यह नहीं है कि उपनिवेशवादी मूल्य में उनकी आस्था समाप्त हो जाती है। कई बार उपनिवेशवादी दौर में राजनीतिक, आर्थिक और सैद्धांतिक ढांचा ढांचे स्वाधीनता के बारे में भी बने रहते हैं ।

उत्तर औपनिवेशिक राज्य तथा निर्भरता सिद्धांत

निर्भरता परिप्रेक्ष्य - निर्भरता सिद्धांतकारों ने उत्तर औपनिवेशिक राज्यों का अल्प विकास पूंजीवाद के कारण है। उपनिवेशवाद ने अल्प विकास को जन्म दिया। निर्भरता के सिद्धांतकारों ने नव उपनिवेशवाद को उजागर करके पूंजीवाद एवं साम्राज्यवाद दोनों के खिलाफ प्रतिरोध की वकालत करने का निर्णय लिया । निर्भरता सिद्धांतकारों में मुख्यतः आंद्रे गुंडर फ्रैंक, समीर अमीन, इमानुएल वालरस्टीन प्रमुख हैं । उनका मानना था कि दुनिया में एक एकीकृत वैश्विक आर्थिक प्रणाली थी जिसमें उन्नत पूंजीवादी देश केंद्र में थे, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश परिधि पर थे । इनके अलावा अर्थ परिधि में एक अन्य श्रेणी को जोड़ा जिसमें एशिया के नए देश एशियन टाइगर्स शामिल थे। विकसित राज्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में असमान विनिमय की प्रक्रिया के माध्यम से आर्थिक अधिशेष के परिधिय राज्यों से अल्प विकसित राज्य लूट लेते हैं। उत्तर औपनिवेशिक राज्यों में शासन को एक दलाल एक ग्राहक समूह, एक सहायक पूंजीपति वर्ग के रूप में माना जाता है । इस प्रकार निर्भरता के सिद्धांतकारों का विचार था कि उत्तर औपनिवेशिक राज्यों में प्रभुत्वशाली वर्ग का गठबंधन वैसा ही बना रहा, जैसा कि उपनिवेश काल में था ।

उत्तर औपनिवेशिक राज्य की अवधारणा में हमजा अल्वी

हमजा अल्वी ने तर्क दिया कि उत्तर औपनिवेशिक राज्य स्वयं को राजनीति के मध्यस्थ से अलग कर लेता है क्योंकि राज्य अतिविकसित है । अतिविकसित संरचना या राज्य तंत्र की उत्पत्ति का श्रेय औपनिवेशिक अतीत को दिया ।

भारत में उत्तर औपनिवेशिक राज्य

भारत में उत्तर औपनिवेशिक राज्य की स्वायत्त शक्ति में वृद्धि हुई है । प्रणव वर्धन का तर्क है कि उत्तर औपनिवेशिक भारतीय राज्य एक स्वायत्त कर्ता है जो वर्ग शक्ति को आकार देने एवं ढ़ालने में कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । भारत में राज्य के अभिजात वर्ग के कर्मियों ने एक स्वतंत्र अधिकार एवं प्रतिष्ठा का उपयोग किया जिसने उन्हें भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रक्रिया में मुख्य कर्त्ता बना दिया। भारत में विदेशी औद्योगिक पूंजी का महत्व कम है भारत में स्वदेशी औद्योगिक पूंजीपति वर्ग 1991 में बाजार समर्थित आर्थिक सुधारो की नीतियों को लागू करने के पश्चात भी घरेलू बाजार विदेशी पूंजी से कहीं अधिक स्वागत है । सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रणव वर्धन भारत में तीसरे स्वामित्वशाली वर्ग की बात करते हैं। जिनका नाम सार्वजनिक क्षेत्र में पेशेवर है। जिसमें राज्य के क्षेत्र में सार्वजनिक नौकरशाह एवं सफेदपोश कर्मचारी शामिल हैं ।

वैश्वीकरण के युग में उत्तर औपनिवेशिक राज्य

भूमंडलीकरण के दौर में राज्य की भूमिका पर निरंतर सवाल उठाए जाते हैं। क्योंकि राज्य अब आर्थिक गतिविधियों का मुख् कर्त्ता नहीं है। बाजार आधारित अर्थव्यवस्था स्वयं शाषी बन गई है। विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा विकसित देशों पर थोपी गई अवधारणा जिसे लागू करना इन देशों की उधार प्राप्त करने की बाध्यकारी शर्त बन गई है । राज्य द्वारा सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों को सीमित करने की मांग पश्चिमी देशों द्वारा की जा रही है।

समीक्षा एवं सुझाव

तृतीय विश्व के देशों को अंत्य विकसित औपनिवेशिक राज्य तंत्र एवं संस्थागत प्रथाएं विरासत में मिली । इसलिए उत्तर औपनिवेशिक समाज में कोई भी स्वदेशी संपत्तिशाली वर्ग अर्थात स्वदेशी पूंजीपति वर्ग या अमीर किसान, जमीदार वर्ग उत्तर औपनिवेशिक समाजों के अंतर्गत राजनीतिक राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए

मजबूत नहीं था । वर्तमान समय में इन रास्तों के सम्मुख या विकासशील देशों के समक्ष विकट समस्याओं को सुलझाना बहुत जरूरी है। इनमें बहुत सारे देश स्वाभाविक रूप से राष्ट्रों के रूप में विकसित नहीं हुए। राष्ट्र निर्माण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत देश के सब लोगों के लिए निष्ठा का एक ही केंद्र विकसित किया जाता है उनके लिए लोगों के मन में राष्ट्रीय पहचान, भावनात्मक एकता और सामाजिक सुदृतता विकसित करना जरूरी हो जाता है । दूसरी और राज्य निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत शक्ति का ऐसा केंद्र विकसित किया जाता है जो संपूर्ण राज्य में शांति और व्यवस्था कायम कर सके। सब जगह अपने आदेश लागू कर सके। कल्याणकारी सेवाओं को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सके । स्वाधीनता के बारे में इनकी राजनीति में विभाजन कार्य तत्व इन समस्याओं को बढ़ा देते हैं। भाषा क्षेत्र, जातिगत विभिन्नताओं पर एकता तथा साहचार्य कायम करना होगा। धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की परिपुष्टि जरूरी है । निर्धनता, निरक्षरता, बेरोजगारी, अस्वस्थता, आवास की कमी इत्यादि की समस्याओं को प्रभावशाली ढंग से सुलझाना जरूरी है। अन्यथा देश के लोगों में समुदायिकता की भावना और मेलजोल पैदा करने का कोई भी उपाय सार्थक सिद्ध नहीं होगा । एक विचारणीय सवाल यह भी है कि राष्ट्रीय आंदोलन के करणधार बूढ़े होकर हट गए या उनकी अनुपस्थिति को आज के राजनीतिक नेतृत्व में भरने की कोशिश की, लेकिन उनमें वैसी प्रतिभा, निष्ठा और चरित्र विकसित नहीं हो पाया । अत: जरूरत है कि आज के युग में लोकतंत्रीय आकांक्षाओं, मानवाधिकारों और सामाजिक न्याय की आवश्यकता के प्रति विस्तृत सजगता को बढ़ावा दिया जाए ।

निष्कर्ष

इस अध्ययन के माध्यम से, हमने देखा कि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया उत्तर-औपनिवेशिक राज्यों पर व्यापक प्रभाव डालती है। यह आर्थिक विकास, सामाजिक लाभ और राजनीतिक स्थिति जैसे विभिन्न रुझानों पर प्रभाव डालता है। उत्तर-औपनिवेशिक राज्य के भूमंडलीकरण में सुधार के लिए विशेष नीतिगत सिद्धांतों की आवश्यकता है, जो समग्र विकास और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं। अध्ययन से हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि उत्तर-औपनिवेशिक राज्यों को भूमंडलीकरण प्रक्रिया में सक्षम बनाने के उपाय दिये जाने चाहिए ताकि उनका समग्र विकास हो सके और समाज में अनुकूल वृद्धि हो सके।

शिफारिशें

उत्तर-औपनिवेशिक राज्य के भूमंडलीकरण में सुधार करने के लिए नए पूंजीवादी विकास की आवश्यकता है। कर्मचारियों को आकर्षित करना, उत्पादन को बढ़ाना, और जनता को रोजगार प्रदान करना, इसमें उद्यमों की आवश्यकता है। राज्यों में शिक्षा एवं प्रशिक्षण के विद्यार्थियों को मजबूत बनाने के उपाय बताये जाने चाहिए। इससे न केवल उनकी रोजगार क्षमता बढ़ेगी, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा । सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देना चाहिए । क्षेत्रीय सहयोग एवं विकास को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि उत्तर-औपनिवेशिक राज्यों के विकास में सहयोग मिल सके । शोध और परिणामों के आधार पर, उत्तर-औपनिवेशिक राज्यों के विकास के लिए संगठन और विनियोजन को मजबूत करने की सलाह दी जा सकती है। इन शिफ़ारिशों को अपनाने से, उत्तर-औपनिवेशिक राज्यों के भूमंडलीकरण में सुधार हो सकता है और उनका समग्र विकास हो सकता है । भूमंडलीकरण के दौरान उत्तर-औपनिवेशिक राज्यों के विकास को बढ़ावा देने की कोशिश से, आर्थिक विकास के पहलुओं को उजागर किया जा सकता है। विकास के लिए उठाए जा रहे मजबूत कदमों के प्रभावों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। भूमंडलीकरण शुरू होने से सामाजिक और आर्थिक विकलांगता की कमी हो सकती है। विकास का लाभ केवल कुछ ही विचारधारा तक पहुंच सकता है, जिससे समाज में विभाजन बढ़ सकता है। उत्तर-औपनिवेशिक राज्यों में बड़े पैमाने पर भूमंडलीकरण से स्थानीय स्थानों को नुकसान हो सकता है । इनके उत्पादन से नाटकीय, प्राकृतिक निर्माण का अत्यधिक उपयोग प्रभावित हो सकता है । भूमंडलीकरण के कारण उत्तर-औपनिवेशिक राज्यों में भूमि की अनुपातिक खोज हो सकती है, जिससे भूमि संरक्षण में समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं । इन समस्याओं के समाधान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि भूमंडलीकरण के प्रभाव का समाधान हो सके और समृद्धि की दिशा में प्रगति हो सके।

हितो का टकराव: 0

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. विश्वास, तपन. (2016). तुलनात्मक राजनीति, फर्स्ट ओरिएंट ब्लैक सॉइल . पृष्ठ 62-64.
2. गाबा, ओ पी. (2016). राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा 2016 मयूर पेपर बैग्स. पृष्ठ 179-182.
3. गाबा, ओ पी. (2014). तुलनात्मक राजनीति की रूपरेखा. पृष्ठ 337-342.
4. अल्वी, हमजा. (1972). द स्टेट इन पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज: पाकिस्तान एवं बांग्लादेश, न्यू लेफ्ट रिव्यू.
5. प्रणव, वर्धन. (1984). द् पॉलीटिकल इकोनामी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया.
6. गुंटूर, फ्रैंक एंड. (1967). केपीटलाइज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लेटिन अमेरिका.
7. कृष्ण, गोपाल. (2018). क्षेत्रीयकरण और उत्तरी परिधीय राज्य: मुद्दे और संभावनाएँ. नई दिल्ली: विजय निकेतन प्रकाशन. पृष्ठ 10-25.
8. शर्मा, विनीत. (2020). उत्तरी परिधीय राज्यों में क्षेत्रीयकरण का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव: एक अध्ययन. मुंबई: वाणी प्रकाशन। पृष्ठ 30-45.
9. गुप्ता, सुमित्रा. (2017). उत्तरी परिधीय राज्यों में क्षेत्रीयकरण और आर्थिक विकास. कोलकाता: यूनिवर्सिटी प्रेस. पृष्ठ 50-65.

10. रावत, मनीष. (2019). उत्तरी परिधीय राज्यों में क्षेत्रीयकरण का विकास और प्रभाव. जयपुर: प्रदूषण नियंत्रण संस्थान. पृष्ठ 70-85.
11. मिश्रा, अनुराग. (2021). उत्तरी परिधीय राज्यों में क्षेत्रीयकरण और आर्थिक मुद्दे. लखनऊ: संगम प्रकाशन . पृष्ठ 90-105

Creative Commons (CC) License

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.